RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 024
दि. 27.10.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

भारत और ASEAN की रणनीतिक साझेदारी मजबूत, पीएम मोदी ने 47वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में साझा की दिशा और दृष्टि

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 47वें ASEAN शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए भारत और ASEAN के बीच गहन सहयोग और स्थायी साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ASEAN मिलकर दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दोनों पक्षों की शक्ति, ऐतिहासिक जुड़ाव और साझा हितों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की सफल मेजबानी कर रहे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी और इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच संबंधों की मजबूती का महत्व रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ASEAN को भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" का आधार बताते हुए कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा है और अपने मित्र देशों के साथ हर संकट में मजबूती से खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि भारत-ASEAN सहयोग केवल कूटनीतिक संबद्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत किसी भी स्थिति में अपने साझेदारों को अकेला नहीं छोड़ता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत-ASEAN सहयोग अनिवार्य है।

इस सम्मेलन में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए तिमोर-लेस्ते को ASEAN का 11वां सदस्य घोषित किया गया। पीएम मोदी ने तिमोर-लेस्ते का स्वागत करते हुए कहा कि यह ASEAN का 26 वर्षों में पहला विस्तार है। लगभग 14 लाख की आबादी वाला तिमोर-लेस्ते अब ASEAN के व्यापार, निवेश और विकास ढांचे का हिस्सा बनेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से पूरे क्षेत्र में सहयोग, निवेश और विकास के नए अवसर खुलेंगे। सम्मेलन में थाईलैंड की महारानी मां के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ASEAN केवल भूगोलिक निकटता नहीं, बल्कि साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के आधार पर जुड़े हैं।

सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मलेशिया पहुंचे। यह उनकी व्हाइट हाउस में दोबारा सत्ता में लौटने के बाद एशिया की पहली आधिकारिक यात्रा मानी जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार, यह यात्रा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में भारत-ASEAN समुद्री सुरक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक, निवेश और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त प्रयासों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि ASEAN और भारत का सहयोग समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भी भारत-ASEAN साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि भारत और ASEAN केवल आर्थिक या सुरक्षा साझेदार नहीं, बल्कि एक साझा दृष्टि और साझा मूल्यों के आधार पर मजबूती से जुड़े हुए हैं।

विशेष रूप से, सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा संसाधनों के सतत प्रबंधन, डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग, निवेश और व्यापार संवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन के समाधान और शिक्षा-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। यह शिखर सम्मेलन भारत और ASEAN के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रतीक माना जा रहा है और आने वाले वर्षों में इस सहयोग के सकारात्मक परिणाम पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर दिखाई देंगे।

यह शिखर सम्मेलन भारत-ASEAN संबंधों के लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास की दिशा में रणनीतिक निर्णयों का मंच बना, बल्कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास, साझेदारी और सहयोग की नींव को भी मजबूत किया। आने वाले वर्षों में इस साझेदारी से समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कुर्मी क्षत्रिय सभा का भव्य आयोजन 31 अक्टूबर को, मेधावी छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा सम्मान

(जीएनएस)। बरेली। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी कुर्मी क्षत्रिय सभा ने पूरी कर ली है। यह आयोजन 31 अक्टूबर को ब्रह्मपुरा स्थित सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास परिसर में होगा। इस अवसर पर कुर्मी समाज एकजुट होकर अपने आराध्य पुरुष के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लेगा। कार्यक्रम का स्वरूप सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक तीनों ही दृष्टि से विशेष होगा। रविवार को सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की। सभा के अध्यक्ष केपी सेन गंगवार ने बताया कि समारोह का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से किया जाएगा। इसके बाद समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी सरदार पटेल स्मारिका का विमोचन करेंगे। यह स्मारिका कुर्मी समाज के गौरव, उनके योगदान और भविष्य की योजनाओं का दस्तावेज होगी। अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस एकता और अखंडता की नींव रखी, वही भावना आज समाज के हर वर्ग में फिर से जाग्रत करनी है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के युवाओं और आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की भावना जगाना है।

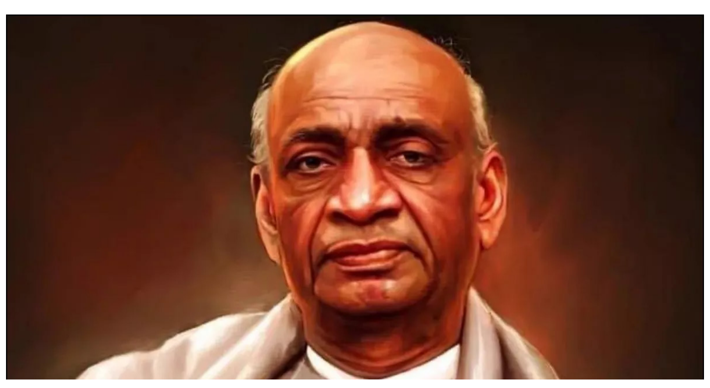

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद छत्रपाल गंगवार उपस्थित रहेंगे। उनके साथ जिले की राजनीति और समाजसेवा से जुड़े अनेक गणमान्य अतिथि भी समारोह में शिरकत करेंगे। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक डॉ. एम.पी. आर्य, पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह गंगवार (वीरू), अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्रुति गंगवार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऐबरन कुमार गंगवार, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, नीरू पटेल, उषा गंगवार, और नरेन्द्र पाल सिंह गंगवार जैसी प्रतिष्ठित हस्तियाँ शामिल होंगी। समाज की नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए इन अतिथियों द्वारा अपने अनुभव और विचार भी साझा किए जाएंगे। कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण होगा समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। मुख्य अतिथि इन प्रतिभावानों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि यह सम्मान समारोह समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रतीक होगा। युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया जाएगा कि ज्ञान और अनुभव, दोनों का संगम ही समाज को मजबूत बनाता है। सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अवसर पर कुर्मी क्षत्रिय सभा की वर्तमान गतिविधियों, संगठन विस्तार की योजनाओं और सामाजिक उत्थान से जुड़े भविष्य के संकल्पों पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकजुटता पर कार्य करने की रूपरेखा तय की जाएगी। समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के अलावा महिलाओं की भागीदारी पर भी विशेष बल दिया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह, आर.सी. लाल, ऑडिटर मनोज बाबू, मीडिया प्रभारी देश दीपक गंगवार, सदस्य अरविंद पटेल, डॉ. उग्रसेन गंगवार, अमित गंगवार, खेमेन्द्र पाल सिंह, मनोहर लाल गंगवार, और भद्रपाल गंगवार मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरदार पटेल की जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाजिक चेतना का पुर्नजागरण है।

कुर्मी क्षत्रिय सभा के इस आयोजन को लेकर शहर ही नहीं, आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह का माहौल है। समाज के लोग मानते हैं कि सरदार पटेल का जीवन समर्पण, सेवा और स्वाभिमान का प्रतीक था। उनके आदर्शों को जनमानस तक पहुँचाने के लिए इस आयोजन के माध्यम से एक नई सामाजिक एकता की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह से समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और जातीय एकजुटता के लिए शपथ दिलाई जाएगी।

सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरदार पटेल का जन्म केवल एक नेता के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे भारत की अखंडता के प्रतीक और एकता के सजीव प्रतीक थे। उनके सिद्धांत आज भी समाज को एक दिशा और दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए यह जयंती समारोह ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा।

ब्रिटेन में भारतीय मूल की युवती से नस्लीय हमले के बाद दुष्कर्म, 'इंडिया वापस जाओ' कहकर किया गया अत्याचार

(जीएनएस)। लंदन। ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिलाओं पर बढ़ते नस्लीय हमले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर इंग्लैंड के वॉल्सॉल इलाके में भारतीय मूल की एक युवती से निर्मम दुष्कर्म की घटना ने पूरे ब्रिटेन को झकझोर कर रख दिया है। पीड़िता के अनुसार, हमलावरों ने न केवल उसके साथ दरिंदगी की बल्कि उसे अपमानित करते हुए 'इंडिया वापस जाओ' जैसी नस्लीय टिप्पणियां भी कीं। इस घटना ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच भारी आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया है।

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बताया कि यह अपराध "नस्लीय रूप से प्रेरित हमला" था। शनिवार शाम पार्क हॉल इलाके से पुलिस को पीड़िता का फोन मिला, जिसके बाद फोर्स ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक की सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए लोगों से पहचान में मदद मांगी है। फुटेज में दिखने वाला आरोपी लगभग 30 वर्ष का श्वेत पुरुष है, जिसके बाल छोटे हैं और जिसने घटना के समय गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे।

जांच का नेतृत्व कर रहे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने बताया कि यह एक "बेहद घृणित अपराध" है, और अपराधी को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि "हमारी जांच टीमें इलाके के घर-घर जाकर पूछताछ कर रही हैं, सबूत जुटाए जा रहे हैं, और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके से नमूने इकट्ठा कर रहे हैं।" उन्होंने जनता से अपील की कि अगर किसी ने उस समय उस इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

इस घटना को लेकर ब्रिटेन के भारतीय समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। सिख फेडरेशन UK ने इस मामले में पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने बताया कि पीड़िता एक पंजाबी युवती है, जिसके घर में घुसकर हमलावर ने हमला किया। संगठन ने कहा कि "यह सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं है, बल्कि यह नस्लीय नफरत की पराकाष्ठा है।" सिख फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि वेस्ट मिडलैंड्स में पिछले दो महीनों में भारतीय मूल की दो युवतियों के साथ नस्लीय दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर पाई।

दरअसल, इसी क्षेत्र में सितंबर महीने में ओल्डबरी की एक सिख महिला के साथ भी इसी तरह का बलात्कार हुआ था। वह भी सुबह के समय अपने घर से बाहर निकल रही थी, जब एक अज्ञात युवक ने उस पर हमला किया था। दोनों घटनाओं की प्रकृति और लोकेशन लगभग समान होने के कारण अब पुलिस को शक है कि दोनों वारदातें एक ही व्यक्ति या गिरोह द्वारा की गई हों।

ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिलाओं पर लगातार बढ़ते नस्लीय हमलों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल की महिलाओं के खिलाफ घृणास्पद अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई विशेषज्ञ इसे ब्रिटेन में उभरते सामाजिक ध्रुवीकरण और नस्लीय तनाव का परिणाम मान रहे हैं।

ब्रिटिश संसद में भी अब यह मुद्दा उठने लगा है। भारतीय मूल के सांसदों ने कहा कि "अगर सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो यह ब्रिटेन के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा।" वहीं, भारत सरकार ने भी लंदन स्थित अपने उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों से इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है।

फिलहाल पीड़िता को मेडिकल और मानसिक सहायता दी जा रही है। पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि वह अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। लेकिन यह घटना इस बात की कठोर याद दिलाती है कि ब्रिटेन जैसे विकसित देश में भी नस्लीय घृणा की आग अब भी जीवित है, और इसके सबसे ज्यादा शिकार वे हैं जो इस देश में मेहनत, सपनों और सुरक्षा के साथ जीना चाहते हैं।

पंजाब में पराली संकट गहराया: अब तक 266 एफआईआर, 17 लाख का जुर्माना, हवा फिर जहरीली बनी

(जीएनएस)। चंडीगढ़। पंजाब में पराली जलाने की समस्या पर सरकार की तमाम सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। रविवार को इस सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए। राज्यभर में एक ही दिन में 122 नए केस सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 743 हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है — अब तक 266 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 16 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 296 मामलों में किसानों की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है, जो उनके लिए भविष्य में सरकारी लाभ या ऋण प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।

सबसे अधिक पराली जलाने के मामले तरनतारन जिले से सामने आए हैं, जहां अब तक 224 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद अमृतसर में 154, फिर फिरोजपुर, बठिंडा, लुधियाना और मानसा जैसे जिलों में पराली जलाने के सैकड़ों मामले रिपोर्ट हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, जैसे-जैसे धान की कटाई अपने चरम पर पहुंच रही है, आने वाले दिनों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। पिछले छह दिनों में ही राज्य में 328 नई घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सरकार ने पहले ही पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं। बावजूद इसके, खेतों में

धधकती आग की लपटें और धुएं के गुबार लगातार आसमान में उठ रहे हैं।

पराली के धुएं से हवा जहरीली

पंजाब के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को जालंधर का AQI 439 रिकॉर्ड किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। बठिंडा का AQI 321, लुधियाना का 260, अमृतसर का 257, पटियाला का 195 और मंडी गोबिंदगढ़ का 153 रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ हफ्तों में और बिगड़ सकती है यदि पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुकीं।

दिल्ली भी पराली की मार से बेहाल

दिल्ली-एनसीआर की हवा भी एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। राजधानी का AQI कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली की हवा में पीएम-2.5 कणों का स्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि प्रदूषण की पूरी जिम्मेदारी किसानों पर डालना गलत है, क्योंकि फसल कटाई से पहले ही दिल्ली का प्रदूषण स्तर ऊंचा था।

किसानों का तर्क है कि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था देने में असफल रही है। पराली को न जलाने पर कोई प्रभावी आर्थिक या तकनीकी समाधान नहीं दिया गया। किसानों का कहना है कि पराली हटाने की मशीनें महंगी हैं और सरकार द्वारा सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा रफ्तार से पराली जलाई जाती रही तो नवंबर के पहले हफ्ते तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर की हवा 'गंभीर' श्रेणी में स्थायी रूप से आ जाएगी, जिससे सांस, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।

सरकार ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और जिन किसानों ने वैकल्पिक उपाय अपनाए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि खेतों में धुआं अब भी उठ रहा है, और पंजाब की हवा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की सांसें भी इस धुंध में घुट रही हैं।

आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सांसद जियाउर्रहमान बर्क

(जीएनएस)। संभल। संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर बड़ा बयान देते हुए इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब चुनाव से पहले लोगों को भड़काने और माहौल बिगाड़ने की योजना के तहत किया जा रहा है। सांसद ने कहा, 'हमारी आस्था हमारे दिल में है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है।' बर्क ने कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है। अगर ईमानदारी से जांच की जाए, तो इसमें मुस्लिम समाज का कोई हाथ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज हमेशा से दूसरे धर्मों की आस्था का सम्मान करता आया है और कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। सपा सांसद ने कहा, 'जहां हम अपने मजहब का आदर करते हैं, वहीं दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं, भले ही हम उन्हें न मानते हों। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।' बर्क ने दोनों समुदायों से अपील की कि किसी के नाम पर आपस में झगड़ा न करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक विवादों से देश और समाज दोनों को नुकसान होता है। ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए जो कौम और मुल्क दोनों के हित में हों। मदरसे में बच्ची से 'खास तरह का प्रमाणपत्र' मांगे जाने की खबरों पर भी सांसद बर्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके समाज के किसी भी मदरसे में ऐसी प्रथा न तो सुनी गई है और न ही मान्य है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। बर्क ने साफ कहा, 'हमारे मजहब में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, और तालीम के लिए किसी से इस तरह का सर्टिफिकेट मांगना नाजायज और गलत है।

संपादकीय

बिहार में तेजस्वी के नाम पर मुहर मजबूरी भरी स्वीकृति

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथियां जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनाव के सतरंगी रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में आखिरकार उस घोषणा का रंग भी देखने को मिल ही गया, जिसका सबको इंतज़ार था। आखिरकार तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है। यह निर्णय 'देर आए, दुरुस्त आए' की कहावत को चरितार्थ करता है। लंबे समय से इस पर राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस क्या तेजस्वी के नेतृत्व को खुले तौर पर स्वीकार करेगी या नहीं? अंततः उसने तेजस्वी पर भरोसा जताया, पर यह भरोसा एक प्रकार की मजबूरी भरी स्वीकृति भी लगती है, न कि उत्साहपूर्ण गठबंधन की रचनात्मक एकजुटता। यह घोषणा कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की ओर से की गई। इसी के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआइपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। अशोक गहलोत की इस घोषणा से पता चलता है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है, उसने मुख्यमंत्री का चेहरा अनिच्छा से ही उजागर नहीं किया था, इस अनिच्छा से यही झलका कि कांग्रेस अभी भी गठबंधन राजनीति के धर्म का मर्म समझने में उलझी है, यह राहुल गांधी की नाकाम राजनीति का भी द्योतक है, ऐसे मामलों में वे अपरिपक्वता का ही परिचय देते रहे हैं। क्या कांग्रेस ऐसा कुछ मानकर चल रही थी कि महागठबंधन के जीतने की सूरत में तेजस्वी यादव के अतिरिक्त अन्य कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है? उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह बिहार में अपनी राजनीतिक महत्ता बनाए रखने के लिए राजद पर ही निर्भर है। उसकी ऐसी ही निर्भरता अन्य राज्यों में भी वहां के क्षेत्रीय दलों पर है। जब तक वह अपने बलबूते चुनाव लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा लेती, तब तक उसे उन्हें दबाव में लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसके पास न प्रभावशाली चेहरा है, न जनाधार। हाल के चुनावों में उसका प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था कि वह नेतृत्व की भूमिका की बजाय सहयोगी भूमिका निभाए। तेजस्वी यादव के रूप में राजद आज बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। यह भी एक वास्तविकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जनाधार खिसक रहा है, तेजस्वी उस रिक्त स्थान को भरने की क्षमता रखते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ वर्षों में अपने नेतृत्व को निखारा है। उन्होंने 'नौकरी, विकास और सम्मान' जैसे मुद्दों को अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया है। उनकी भाषा में युवाओं की बेचैनी, बेरोज़गारी का दर्द और अवसरों की तलाश झलकती है। बिहार के युवा अब जातीय राजनीति से ऊपर उठकर रोज़गार और जीवन की गुणवत्ता के सवाल पूछने लगे हैं, और तेजस्वी इन्हीं सवालों को अपनी ताकत बना रहे हैं। हाल के वर्षों में उनके तेवर में जो परिपक्वता आई है, वह बताती है कि वे अब सिर्फ 'लालू के पुत्र' नहीं, बल्कि स्वयं का राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। उनका 'जनादेश' अब सिर्फ परंपरा या पारिवारिक विरासत पर आधारित नहीं है, बल्कि नये बिहार की आकांक्षाओं से जुड़ने की कोशिश है।

एनडीए ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिए थे और सीट बंटवारे की घोषणा कर दी थी। लेकिन, उन्होंने किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया है। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाकर एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश की है। यह चुनाव बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प है और इसमें वादों का दौर भी जारी है। नीतीश सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी जनता से कई वादे किए हैं। महागठबंधन का घोषणापत्र आने वाला है, जिसमें कई बड़े वादे होने की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस वादे पर भरोसा करती है और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। ताजा परिदृश्यों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा के विकास की राजनीति ही बढ़त बनाये हुए है। भाजपा ने बिहार में धीरे-धीरे अपना जनाधार बढ़ाया है, अब भी वह स्वतंत्र चुनाव न लड़कर क्षेत्रीय दलों के सहारे आगे बढ़ रही है। भले ही नीतीश कुमार, जिन्होंने वर्षों तक 'सुशासन बाबू' की छवि से राजनीति की, अब थके हुए और अविश्वसनीय से प्रतीत होने लगे हैं।

राहुल गांधी की नाकाम राजनीति, साख और कांग्रेस का समर्थन दरक रहा

> नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने से जुड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी उसके विरोध में अड़ गए कि इसके जरिये संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। उनसे सवाल बनता है कि क्या 1958 में केंद्र की सरकार उन शरणार्थियों से वादा करके संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही थी? राहुल गांधी का यह रवैया कुछ और नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही है। इससे न केवल उनकी साख प्रभावित हो रही है, अपितु कांग्रेस का समर्थन भी दरक रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त, 2011 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश की तरक्की में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन इससे निपटने के लिए उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। मनमोहन सरकार में भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक बड़े मामले सामने आए थे। इनमें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में घोटाले के मामले सुर्खियों में छाए रहे। इस पर जब उनसे सवाल किया जाता तो वह कहते कि गठबंधन सरकारों की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं।

केंद्र में जब उनकी सरकार बदली तो भ्रष्टाचार से निपटने का रवैया भी पूरी तरह बदल गया, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भ्रष्टाचार पर उनका लचर रवैया भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का एक कारण बना। नरेन्द्र मोदी ने देश की कमान संभालने के पहले ही कह दिया था कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा।' मोदी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने इस संकल्प को बार-बार दोहराया भी। उन्होंने 2016 में कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और मैं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा कर ही दम लूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह कथित राजनीतिक विवशता का रोना न रोते हुए मोदी देश में नई प्रशासनिक संस्कृति की नींव डाल रहे हैं।

मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से परेशान कांग्रेस समेत एक दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि केंद्र सरकार सीबीआइ, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल है कि यदि दुरुपयोग हो रहा है तो अदालतें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के कोई समझौता न करने वाले रवैये के कारण ही नेहरू-गांधी परिवार को यह अहसास

हुआ है कि उन्हें ऐसे मामलों में कोई राहत नहीं मिलने वाली। ध्यान रहे कि नेशनल हेराल्ड से संबंधित मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका के आधार पर मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही शुरू हुआ था।

नेहरू-गांधी परिवार ने शायद सोचा होगा कि मोदी सरकार में उन्हें इस मामले में रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों इस केस में जमानत पर हैं। उनका सत्ता में लौटने का सपना भी दूर-दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा। इस निराशा से उपजी कुंठा के कारण ही राहुल गांधी का अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं रह गया है। उन्होंने सत्य और असत्य का भेद मिटा दिया है। वे मोदी के खिलाफ धमकी, गाली-गलौज और अत्यंत अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। इसके चलते उन्हें कई मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लगता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं।

उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ऐसे रवैये से राजनीतिक विमर्श का स्तर रसातल में ही क्यों न चला जाए या संसद की गरिमा तार-तार हो जाए। अपने बड़बोलेपन में उन्हें यह भी अहसास नहीं रहता कि वे क्या कह रहे हैं। कभी वे भारतीय राज्य पर सवाल उठाते हैं कि भारत राष्ट्र न होकर महज राज्यों का एक संघ है तो कभी कहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा-आरएसएस से ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यव्यवस्था से है। इसी से राहुल गांधी की मानसिकता को समझा जा सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाए। जब आयोग ने राहुल से कहा कि वे अपने आरोपों के पक्ष में शपथपत्र दें तो राहुल उसके लिए राजी नहीं हुए। इसी से संकेत मिला कि उनके आरोपों में कितना दम था। महात्मा गांधी ने एक समय 'सत्य के साथ प्रयोग' किए थे, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने असत्य को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। जब उनके आरोप नहीं टिकते तो वे तुरंत नया राग छेड़ने लगते हैं। जब आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर निशाना साधने से बात नहीं बनी तो वे कहने लगे कि जदयू-भाजपा की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया।

ऐसा आरोप मढ़ते हुए राहुल भूल गए कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के कुख्यात जंगलराज का हिस्सा उनकी पार्टी कांग्रेस भी रही है। लालू सरकार में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय आठ हजार रुपये थी, वह नीतीश राज में बढ़कर 68 हजार रुपये हो गई है। वस्तुतः कुछ भी कह देना और उसके पक्ष में कोई साक्ष्य न देना राहुल गांधी की शैली बन गई है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने श्रीनगर में कहा था कि 'देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। उनका यौन शोषण हो रहा है, लेकिन पुलिस उन्हें न्याय नहीं दिला पर रही है।' इन आरोपों के बारे में जानकारी लेने के लिए पुलिस राहुल गांधी के आवास पर तीन बार गई, मगर वे कोई ठोस जवाब और साक्ष्य नहीं दे सके।

नीतिगत मामलों पर भी राहुल गांधी अपरिपक्वता का परिचय देते रहते हैं। मोदी सरकार ने 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून की दिशा में कदम बढ़ाए तो अतिवादी तत्वों के दबाव में राहुल गांधी उसके विरोध में जुट गए। जबकि वास्तविकता यही है कि 1958 और 2003 में खुद कांग्रेस सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आस्था के कारण प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का वादा किया था। मोदी सरकार 2019 में उसी वादे की पूर्ति के प्रयास में लगी थी।

नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने से जुड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी उसके विरोध में अड़ गए कि इसके जरिये संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। उनसे सवाल बनता है कि क्या 1958 में केंद्र की सरकार उन शरणार्थियों से वादा करके संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही थी? राहुल गांधी का यह रवैया कुछ और नहीं, बल्कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही है। इससे न केवल उनकी साख प्रभावित हो रही है, अपितु कांग्रेस का समर्थन भी दरक रहा है।

प्रेरणा

आधा घंटा बारिश : शहर, सत्ता और संवेदना की गीली तस्वीर

बरसात का मौसम बीत चुका था। सरकारी कैलेंडर के अनुसार अब हवा में हल्की ठंडक होनी चाहिए थी, और मौसम विभाग के रडार पर बारिश का कोई निशान नहीं था। आसमान साफ था, सूरज तनिक और तेज हो चला था। शहर धीरे-धीरे गर्मी और धूल में लौटने लगा था कि अचानक कहीं से बादलों का एक झुंड आया — जैसे किसी पुराने दोस्त की बिना बुलाए एंट्री हो जाए। और फिर, बिना किसी भूमिका या औपचारिक अनुमति के, शुरू हो गई आधे घंटे की वह बारिश — एक ऐसी बारिश, जो मौसम की किताब में दर्ज नहीं थी, पर लोगों की यादों में गहराई से उतर गई।

पहले तो लगा कि यह बस कुछ बूँदें होंगी, पर जब बादलों ने गरजना शुरू किया तो लगा जैसे आसमान किसी अधूरे भाषण को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही मिनटों में दिन के उजाले पर अंधेरा छा गया, ऐसा लगा जैसे दोपहर को शाम ने निगल लिया हो। दुकानों के शटर आधे बंद, लोग सड़क किनारे भागते हुए, और हवा में मिट्टी की गंध — शहर अचानक अपनी औपचारिकता भूलकर देहात हो गया था।

लेकिन यह रोमांस जल्दी खत्म हो गया। आधा घंटा बारिश क्या हुई, पूरा शहर पानी में उतर गया। जिन नालियों ने सालभर अपनी चुप्पी साधे रखी थी, उन्होंने अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पानी उबलते हुए गड्ढों से बाहर आने लगा और सड़कों ने झीलों का रूप ले लिया। सरकार के दस्तावेज़ों में तो बरसात पहले ही "संपन्न" घोषित की जा चुकी थी, इसलिए नगर निगम की "पानी

निकासी टीम" भी अब अतीत का हिस्सा थी। आपदा नियंत्रण कक्ष में शिकायतें आने लगीं, पर उनका जवाब देने वाले कर्मचारी सोच में थे कि इस बरसात का नंबर सूची में कहाँ डालें — "पूर्व घोषित नहीं" या "प्राकृतिक दुर्घटना"?

नेताओं का बयान भी आया। उन्होंने जनता से कहा कि ऐसे मौसम में घर से न निकलें। मानो जनता ही बारिश की असली वजह हो। वही पुराना जुमला — "आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।" पर सच्चाई यह थी कि बारिश के पानी में सुरक्षा का कोई नामोनिशान नहीं था। राहगीर गली के पानी में अपने जूते ढूँढ रहे थे, बच्चे छतों से बाल्टी डालकर नीचे तैरते हुए चप्पलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर शहर "लंदन जैसा" दिखाई देने लगा था।

कुछ जागरूक नागरिकों ने तत्काल वीडियो बनाकर अपलोड किए — "देखिए हमारे इलाके में किस तरह से आधे घंटे में नहर बन गई।" फेसबुक पर लाइव, यूट्यूब पर व्यूज़, और व्हाट्सएप पर "सावधान रहिए, यह वीडियो आपके इलाके का भी हो सकता है।" लोगों ने सड़कों की जगह सेल्फी लीं, और प्रशासन ने वीडियो देखकर आंकलन किया कि पानी का बहाव "दृश्य रूप से सामान्य" है।

नगर निगम की गाड़ी देर से रवाना हुई। जो कर्मचारी भेजे गए थे, वे रास्ते में सोच रहे थे कि अगर यह बारिश टल जाती तो शाम तक घर पहुंच जाते। सड़क पर पड़े गड्ढे अब इतने गहरे हो चुके थे कि गाड़ी हिचकोले खाते-खाते खुद शिकायत करने लगी। एक पुराना पेड़ जो महीनों से झुककर जी रहा था, आखिरकार गिर पड़ा — किसी पात्र की तरह जिसने अपने संवाद पूरे कर लिए हों। पर उसे हटाने के लिए अनुमति चाहिए थी, और अनुमति के लिए फाइल, और फाइल के लिए हस्ताक्षर — जो उस समय शायद किसी मीटिंग में व्यस्त थे।

इस आधे घंटे की बारिश ने शहर की सारी योजनाओं को भिगो दिया। नए सीवर प्रोजेक्ट की उद्घाटन तिथि फिर से टली। बजट के नए अनुमान बने। ठेकेदार की मुस्कान गहरी हुई। और जो गड्ढे पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक "मरम्मत योग्य" थे, वे अब "पुनर्निर्माण" श्रेणी में चले गए।

लेकिन इस सारी अफरातफरी के बीच, शहर फिर भी जिंदा था। बच्चे बरसात में नाच रहे थे, कुछ बुजुर्ग अपनी छतों से आसमान को देख रहे थे — जैसे याद कर रहे हों कि कभी बरसात का मतलब सिर्फ़ भीगना होता था, डूबना नहीं। आधे घंटे की इस बारिश ने न केवल सड़कों को गीला किया, बल्कि शहर की आत्मा को भी छुआ। यह बारिश चेतावनी थी, मज़ाक भी, और शायद एक प्रतीक भी — कि व्यवस्था कितनी भी पक्की हो, प्रकृति जब चाहती है, आधे घंटे में सबकुछ बहा ले जाती है।

आख़िरकार बादल चले गए, पानी उतरने लगा, गाड़ियाँ फिर चलने लगीं, और वही रोज़मर्रा की धूल फिर सड़कों पर लौट आई। पर हर राहगीर के मन में यह सवाल रह गया — कि क्या यह सिर्फ़ आधे घंटे की बारिश थी, या आधे घंटे में उजागर हुई हमारी आधी-अधूरी व्यवस्था की कहानी?

अंतिम सांसें लेता माओवाद, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को हाल में कुछ बड़ी सफलताएं मिली हैं। इनमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी एवं पोलित ब्यूरो के सदस्य वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू का दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों सहित 60 माओवादियों का आटोमेटिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कई अर्थों में महत्वपूर्ण था। इनमें से कई जोन एवं डिवीजन स्तर के और कई तकनीकी शाखा के सदस्य थे, जो हथियारों के निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत का काम संभालते थे।

भूपति दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव रहा है और आत्मसमर्पण से पहले सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का सचिव था। भूपति ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, परंतु पार्टी के एकमत न होने से बात आगे नहीं बढ़ पाई। भूपति का आत्मसमर्पण माओवादियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब भूपति ने सशस्त्र संघर्ष को रोकने की बात कही तो उत्तर-बस्तर डिवीजन, माड डिवीजन और गढ़चिरौली डिवीजन के माओवादियों ने उसका समर्थन किया।

इसके बाद दंडकारण्य के माओवादी रूपेश उर्फ कोपा उर्फ सतीश, भास्कर उर्फ राजमन मडावी, माड की सचिव रनीता, पूर्व-बस्तर की सचिव निर्मला सहित 210 साथियों ने 17 अक्टूबर को जगदलपुर में आटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह देश में अभी तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। वहीं, 2025 में अब तक 312 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए तो 1,600 से अधिक आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

माओवादियों के सोच में यह बदलाव अचानक नहीं आया। अगस्त 2024 में माओवादियों के पोलित ब्यूरो ने पार्टी को बचाने के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाने का निर्णय लिया था। सभी बड़े दलों और कंपनियों को छोटे टुकड़ों में बांटकर सुरक्षा बलों से बचने के प्रयास माओवादी लगातार कर रहे थे। इसके बावजूद सुरक्षा बलों के अभियानों से वे सिकुड़ते जा रहे थे। मई 2025 में पार्टी महासचिव बसवराजू अपनी मिलिट्री कंपनी के साथ नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया।

इसके बाद केंद्रीय कमेटी का सदस्य माडेम बालकृष्ण गरियाबंद में और रामचंद्र रेड्डी एवं कोसा भी मारे गए। कई माओवादियों ने विगत दिनों तेलंगाना में आत्मसमर्पण किया। इनमें पूर्व माओवादी किशन जी की पत्नी पद्मावती उर्फ सुजाता, चंदू, विकास आदि शामिल हैं। लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस को आगे बढ़ते हुए देखकर माओवादी सरगना समझ चुके हैं कि जो लड़ाई उन्होंने 1980 में दंडकारण्य में शुरू की थी, वह किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर अहिंसा का रास्ता अपनाया जाए। बावजूद इसके, सोनू और रुपेश ने कहा है कि वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

बदली हुई स्थिति में सरकार के दो कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि क्षेत्र का समुचित विकास हो और दूसरे आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का समुचित पुनर्वास। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी समस्त सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करे, जिन्हें आधार बनाकर माओवादियों ने ग्रामीणों में पैठ बनाई थी। विकास की योजना 'नियाद नेलानार' (आपका अच्छा गांव) जैसी योजनाओं का विस्तार केवल सुरक्षा कैंपों की पांच किलोमीटर की परिधि तक सीमित न रखते हुए ऐसे पूरे इलाकों में कर दें, जहां माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

शिक्षा के आश्रम बनाने, स्वास्थ्य सेवा के लिए अस्पताल या डिस्पेंसरी बनाने की योजनाओं को शीघ्र मूर्त रूप देना होगा, क्योंकि आदिवासियों के लिए वनोपज जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनके उचित दाम एवं उनकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ योजनाएं लागू करने पर भी विचार करना होगा। सड़कों का निर्माण और मोबाइल टावर्स भी लगाए जाएं। ऐसे विकास कार्यों को क्रियान्वित करने में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार यह निगरानी भी करे कि आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों को पुनर्वास नीति का लाभ शीघ्र मिले। उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। यह सब करने के बाद भी उन इलाकों पर सुरक्षा बलों को नजर बनाए रखनी होगी, जहां माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार बसवराजू के मरने के बाद माओवादी अपने नए महासचिव का चुनाव नहीं कर पाए हैं। दंडकारण्य के नए सचिव का भी चुनाव नहीं हुआ है। यही कारण है कि केंद्रीय कमेटी एकजुट होकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और सभी डिवीजन अपनी-अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर युद्धविराम की घोषणाएं कर रही हैं। हालांकि तेलंगाना स्टेट कमेटी ने युद्ध जारी रखने की बात कही है, परंतु वह न केवल स्वयं कमजोर स्थिति में है, बल्कि उसके बड़े सदस्य भी राज्य से बाहर शरण लिए हुए हैं। पूर्व महासचिव गणपति, केंद्रीय कमेटी सदस्य संग्राम, गणेशन्ना, हेमंत बिसरा आदि की तरफ से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ है।

अभी पूरी माओवादी पार्टी नेतृत्वविहीन है तो भारत सरकार अगले वर्ष 31 मार्च तक माओवादियों के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह गई है, जिनमें से केवल तीन जिले ही अत्यंत प्रभावित हैं। इन 11 जिलों में से सात छत्तीसगढ़ के हैं। इनमें नारायणपुर और कांकेर में लगभग समस्त माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। गरियाबंद जिले के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण की बात कही है।

कुछ क्षेत्रों को छोड़कर दंडकारण्य के लगभग सभी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब केवल माओवादियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख देवजी के अलावा, मिलिट्री बटालियन का प्रमुख माडवी हिड़मा और दंडकारण्य कमेटी के कुछ सदस्य शेष हैं, जो शायद अभी आत्मसमर्पण करने या युद्ध जारी करने को लेकर असमंजस में हैं। संभव है कि वे भी सोनू और रूपेश की तरह परिस्थितियों को देखते हुए जल्द ही मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला करें। अगर ऐसा नहीं होता तो भी माओवादी पार्टी केवल एक औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी।

अभियान

रवि योग में डूबते सूर्य देव को अर्घ्य देने से बरसेगी अनंत कृपा: छठ का दिव्य प्रसंग और आस्था की अनंत ज्योति

कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष सदा से ही भारतीय परंपरा में विशेष स्थान रखता आया है, और इस मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला छठ पर्व तो आस्था, तपस्या और श्रद्धा का ऐसा संगम है जिसमें भक्ति का प्रत्येक कण सूर्य की किरणों के साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इस वर्ष यह महान पर्व सोमवार 27 अक्टूबर को पड़ रहा है, जब संध्याकाल में डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा, और मंगलवार 28 अक्टूबर को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। यह पर्व न केवल लोक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सूर्योपासना की वह अनुपम साधना है, जो आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच अदृश्य ऊर्जा का सेतु बन जाती है।

27 अक्टूबर का दिन इस वर्ष अत्यंत शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दिन दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से रवि योग का आरंभ हो रहा है, जो रात्रि भर विद्यमान रहेगा। यह वही पवित्र कालखंड है जब सूर्य देव की उपासना से मानव जीवन में तेज, आरोग्यता, आत्मविश्वास और दिव्यता का संचार होता है। ज्योतिष के अनुसार रवि योग तब बनता है जब चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र से मुक्त होकर सूर्य की ज्योति में स्थापित होता है। यह योग तमोगुण को नष्ट करने वाला और सात्त्विकता को प्रबल करने वाला होता है। इस योग में सूर्य की पूजा करने से मनुष्य के भीतर की दुर्बलताएँ समाप्त होकर आत्मबल और ओज उत्पन्न होता है।

संध्याकाल में जब सूर्य अपने अस्ताचल की ओर अग्रसर होता है, तब उसकी किरणें स्वर्णिम और कोमल हो जाती हैं। उस समय जब श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरयू या किसी सरोवर के तट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो वह दृश्य पृथ्वी पर किसी दिव्य लोक के समान प्रतीत होता है। हाथों में कलश, उसमें जल, दूध और फूलों का मिश्रण, और हृदय में समर्पण की भावना — यह सब मिलकर सूर्योपासना का वह क्षण रचते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा को सृष्टि की ऊर्जा से जोड़ देता है। दिल्ली में इस दिन सूर्यास्त 05 बजकर 40 मिनट पर होगा, और उसी समय डूबते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।

ज्योतिषियों के अनुसार इस बार न केवल रवि योग बल्कि सुकर्मा योग और कौलव करण का भी

शुभ संयोग बन रहा है। सुकर्मा योग कर्म की पवित्रता और सिद्धि का योग है, जो यह संकेत देता है कि इस काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य दीर्घकालिक और फलदायी होगा। कौलव करण में दिया गया अर्घ्य शुभ फलदायी माना जाता है क्योंकि यह करण स्थायित्व और शुद्ध भावनाओं का प्रतीक है। इसके साथ ही अगले दिन तैतिल करण रहेगा जिसमें उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा, और वह करण सफलता, उन्नति और वैभव का द्योतक है।

रवि योग में सूर्य देव को अर्घ्य देने के पीछे गहन दार्शनिक अर्थ छिपा है। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, और आत्मा ही ब्रह्म का अंश है। जब मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देता है, तो वह अपने भीतर की आत्मा को उस परम आत्मा से जोड़ने का प्रयास करता है जो सृष्टि का आधार है। छठ में जब व्रती निर्जल उपवास करते हुए सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते हैं, तो वह केवल बाहरी अनुशासन नहीं होता, बल्कि भीतर की तपस्या होती है। यह तपस्या शरीर के विषों को जलाकर आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब अर्घ्य दिया जाता है, तो वह शुद्ध जल सूर्य की किरणों से स्पर्श होकर पुनः उसी साधक पर परावर्तित होता है, जिससे उसकी काया और आत्मा दोनों दिव्यता से भर जाती हैं।

रवि योग में सूर्य उपासना के अनेकों लाभ बताए गए हैं। यह योग आरोग्य, तेज, बुद्धि, आत्मबल और कीर्ति प्रदान करता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दुर्बल या पापग्रस्त होता है, उन्हें इस योग में सूर्य अर्घ्य देकर विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह योग नेत्र रोग, त्वचा रोग और मानसिक दुर्बलता को नष्ट करता है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि रवि योग में सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक उन्नति प्राप्त होती है, बल्कि आत्मिक जागरण भी होता है।

छठ के समय जब लाखों व्रतीजन तालाबों, नदियों और घाटों पर खड़े होकर सूर्य की ओर मुख करते हैं, तब वे उस आदित्य देव की स्तुति करते हैं जो समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। वह सूर्य न केवल प्रकाश देता है, बल्कि जीवन देता है, चेतना देता है, और कर्म का प्रेरक बनता है। इस दिन जब सूर्य अस्त होता है, तब वह अपने साथ साधक के जीवन की नकारात्मकताओं को भी लेकर जाता है। और जब अगले दिन उगता है, तब वह नई ऊर्जा, नई दिशा और नए जीवन का संदेश लाता है। यही कारण है कि छठ पर्व को "अस्त होते सूर्य को प्रणाम और उगते सूर्य का अभिनंदन" कहा गया है — यह जीवन के दो छोरों का अद्भुत संगम है।

इस प्रकार रवि योग में दिया गया डूबते सूर्य का अर्घ्य केवल एक पूजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संवाद है। यह वह क्षण है जब मनुष्य, प्रकृति और देवत्व एकाकार हो जाते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन के सभी अंधकारों को प्रकाश के हवाले कर देना। और जब अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तब वह नवजीवन की प्रतिज्ञा होती है। छठ महापर्व इसी चेतना का उत्सव है — जहाँ हर प्रार्थना सूर्य की किरण बनकर आसमान में विलीन हो जाती है, और हर श्रद्धा भक्ति के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है।

जो साधक इस रवि योग में श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, उनके जीवन में आरोग्य, समृद्धि, सौभाग्य और आत्मशक्ति की वृद्धि होगी। भगवान भास्कर की कृपा से उनके समस्त कार्य सिद्ध होंगे और उनका जीवन भी उसी तेज से आलोकित होगा, जैसा तेज अस्त होते सूर्य का होता है — शांत, गम्भीर, परन्तु अनंत प्रकाश से पूर्ण। यही छठ की सच्ची अनुभूति है, यही आस्था का शिखर है, और यही सूर्य की अनंत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, कहा—यह पर्व आस्था, अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व की पावन बेला पर प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने श्रद्धा और आस्था से भरे संदेश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों सहित पूरे देश को शुभकामनाएं दीं। दोनों ने अपने संदेशों में इस पर्व को भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संदेश में कहा कि छठ महापर्व न केवल सूर्योपासना का पावन उत्सव है बल्कि यह मानव जीवन में शुद्धता, अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि "यह पर्व हमारे जीवन में ऊर्जस्विता, समृद्धि और सद्भाव का प्रकाश फैलाए। समाज में आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना और अधिक प्रबल हो।" उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी श्रद्धालु श्रद्धा और शुचिता के साथ इस पर्व को मनाएं और जलाशयों की स्वच्छता बनाए रखने में योगदान दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि छठ महापर्व भारतीय आस्था, परंपरा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम प्रतीक है। उन्होंने कहा कि "छठ का व्रत रखने वाली माताओं और बहनों का तप, अनुशासन और अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। यह पर्व केवल पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का उत्सव भी है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाशयों और नदियों की स्वच्छता से जुड़ा यह पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण के रक्षण का संदेश देता है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे श्रद्धा और सेवा की भावना के साथ छठ पूजा में सहभाग करें, जिससे समाज में आनंद, शांति और एकता का वातावरण बने।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रदेशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह आत्मानुशासन का पर्व है जिसमें लोग शुद्ध मन और अंतःकरण से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि "छठ संस्कृति, प्रकृति और सामाजिक एकता का सजीव प्रतिबिंब है। जब घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होकर सूर्य को प्रणाम करता है, तब वह दृश्य भारतीय एकता और सौहार्द का सर्वोत्तम उदाहरण बन जाता है।" उन्होंने भगवान भास्कर से प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हुए कहा कि "छठ पर्व हमें सिखाता है कि जब हम मिलकर प्रकृति की आराधना करते हैं, तो न केवल आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है बल्कि सामाजिक सौहार्द भी सशक्त होता है।"

छठ महापर्व के अवसर पर पूरे प्रदेश में श्रद्धा का माहौल है। नदियों और तालाबों के घाटों पर सजावट और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हजारों श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं। जनमानस में यह विश्वास है कि सूर्योपासना से न केवल जीवन में प्रकाश और ऊर्जा आती है, बल्कि परिवार की सुख-समृद्धि भी बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के नेताओं के इन संदेशों ने इस वर्ष के छठ पर्व को और अधिक आध्यात्मिक और प्रेरणादायी बना दिया है।

67 साल बाद राष्ट्रपति का गीताप्रेस आगमन: राजेंद्र प्रसाद के बाद राम नाथ कोविन्द ने किया दर्शन, पुष्पों से सजा लीला चित्र मंदिर

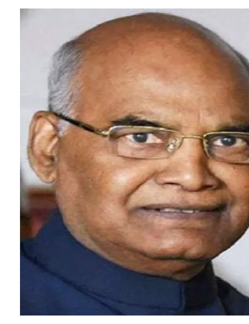

(जीएनएस)। गोरखपुर। 67 साल पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने गीताप्रेस के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गीताप्रेस पहुँचा है। शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने यहां पहुंचकर देवी-देवताओं के दर्शन किए और आम जन को संबोधित किया। इस अवसर पर गीताप्रेस को फूलों से सजाया गया, पूरे परिसर में भव्यता और श्रद्धा का वातावरण दिखाई दिया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गीताप्रेस का पंडाल और मंच पुष्पों से मनमोहक ढंग से सजाया गया था। मंच के सामने ढाई सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। वाराणसी, सूरत, ऋषिकेश और मुंबई से आए विशेष अतिथि भी इस आयोजन में शामिल हुए। राष्ट्रपति, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया, जबकि आम जन के लिए उत्तरी द्वार से प्रवेश और वहीं पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। गीताप्रेस के कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सत्संग भवन में की गई थी। राष्ट्रपति ने सबसे पहले वहीं पहुंचकर कर्मचारियों का अभिवादन स्वीकार किया और फिर लीला चित्र मंदिर में देवी-देवताओं के दर्शन किए। सत्संग भवन में पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया ताकि सभी कर्मचारी समारोह का हिस्सा बन सकें। दर्शन के बाद लीला चित्र मंदिर में राष्ट्रपति के साथ फोटो सेशन हुआ। ट्रस्टियों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें खिंचवाकर इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाया। राष्ट्रपति के विश्राम हेतु मंदिर परिसर में एक विशेष कक्ष तैयार किया गया था। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार लिखे और मुख्य मंच पर जाकर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मुख्य द्वार से लेकर मंच तक तैनात रहे। पूरे कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच श्रद्धा और भव्यता का यह आयोजन संपन्न हुआ। गीताप्रेस, जिसने वर्षों से सनातन संस्कृति के प्रचार और गीता, रामायण, उपनिषद् जैसी अमर कृतियों का प्रसार किया है, उस पवित्र स्थान पर राष्ट्रपति का आगमन एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। 1955 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के उद्घाटन के बाद, राम नाथ कोविन्द का यह आगमन गीताप्रेस के गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया।

चार दिवसीय कुमाऊं दौरे पर आज पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा और यातायात डायवर्जन लागू

(जीएनएस)। नैनीताल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने चार दिवसीय कुमाऊं प्रवास पर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर पूरे नैनीताल, भवाली, भीमताल और हल्द्वानी क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र के लिए विस्तृत वीआईपी रूट और डायवर्जन प्लान जारी किया है। अगले तीन दिनों तक वीआईपी मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि सामान्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर तक निर्धारित है। इस दौरान वे कैंचीधाम समेत कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। सोमवार को कोविंद के आगमन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह "जीरो जोन" में तब्दील हो जाएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर न निकलें।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वीआईपी फ्लीट के हल्द्वानी पहुंचने से लेकर कैंचीधाम तक पहुंचने तक यातायात को क्रमवार रूप से डायवर्ट किया जाएगा। सुबह 11 बजे से फ्लीट के गुजरने तक हल्द्वानी, लालकुआं, ज्योलीकोट, भवाली और नैनीताल के बीच भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह रोक दी जाएगी।

हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जाने वाले वाहनों को भीमताल मार्ग से वाया रामगढ़ भेजा जाएगा। वहीं नैनीताल से हल्द्वानी की ओर लौटने वाले वाहनों को कालाढूंगी मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि फ्लीट के पंतनगर से हल्द्वानी की ओर बढ़ने के दौरान लालकुआं ओवरब्रिज के पास ट्रैफिक रोका जाएगा और फ्लीट के गुजर जाने के बाद ही आवागमन सामान्य किया जाएगा।

फ्लीट के मोतीनगर और गौला पुल क्षेत्र से गुजरते समय हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों को कालटैक्स तिराहा पर रोका जाएगा। वहीं नारीमन तिराहा से गौलापार की ओर जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट कर कालटैक्स मार्ग से भेजा जाएगा। भीमताल से हल्द्वानी की दिशा में आने वाले वाहनों को भीमताल पुल से पहले रोक दिया जाएगा।

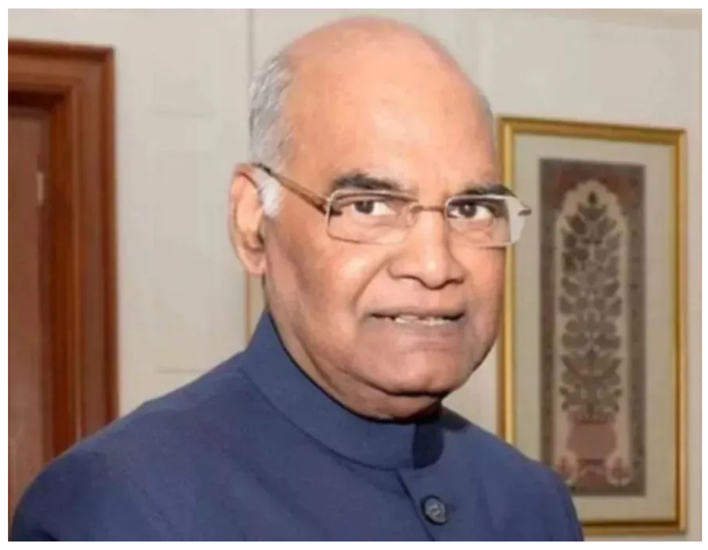

ज्योलीकोट और भवाली क्षेत्र में भी पुलिस ने विशेष योजना लागू की है। फ्लीट के ज्योलीकोट पहुंचने पर भवाली मार्ग को पूरी तरह जीरो जोन घोषित किया जाएगा। इस दौरान भवाली, कैंचीधाम, भीमताल, अल्मोड़ा और रानीखेत से आने वाले वाहनों को क्रमशः बल्दियाखान, नैनीबैंड, घोड़ाखाल और रामगढ़ तिराहा पर रोका जाएगा। फ्लीट के कैंचीधाम मंदिर पहुंचने के समय नैनीताल से भवाली की ओर आने वाले सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय वाहनों को हर 15 मिनट पर सामान्य निकास की अनुमति दी जाएगी, ताकि क्षेत्रीय लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। फ्लीट के कैंचीधाम से वापसी से 15 मिनट पूर्व पुनः जीरो जोन की प्रक्रिया लागू होगी।

फ्लीट के भवाली से नैनीताल की ओर लौटने के दौरान हल्द्वानी और कालाढूंगी रोड से आने वाले वाहनों को रूसी बाईपास से डायवर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार मल्लीताल से फांसी गधेरा, राजभवन की दिशा में फ्लीट के पहुंचने पर तल्लीताल लेक ब्रिज, हनुमानगढ़ी, सूखाताल और चीनाबाबा क्षेत्र में यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। इस दौरान रिक्शा स्टैंड मल्लीताल से लेकर राजभवन तक पूरा मार्ग जीरो जोन रहेगा।

डीआईजी कुमाऊं और एसएसपी नैनीताल ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल को चारों दिशाओं में तैनात किया गया है। संचार प्रणाली, सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी और ड्रोन निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि रखी जाएगी।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें और अनावश्यक रूप से मुख्य सड़कों पर आवाजाही से बचें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से निरंतर अपडेट मिलते रहेंगे और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक हलकों में गहमागहमी है। अनुमान है कि वे इस दौरान नैनीताल राजभवन में ठहरेंगे और कैंचीधाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करेंगे। स्थानीय जनता में भी उनके आगमन को लेकर उत्साह और जिज्ञासा का माहौल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गोझारिया में आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए

▶▶ 'विकसित गुजरात' के निर्माण के लिए 'विकास और विरासत' में संतुलन अनिवार्य : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ "यदि धर्म के साथ विज्ञान हो, तो किसी भी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है"

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात भर में विक्रम संवत 2082 के नववर्ष का उत्सव हर्षोल्लास से मनाने के बाद के दिनों में, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मेहसाणा जिले के गोझारिया में श्री उमिया माताजी मंदिर ट्रस्ट और समस्त पाटीदार समाज की ओर से आयोजित शतचंडी महायज्ञ के पावन अवसर पर सहभागी हुए।

उन्होंने सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव यह कहते हैं कि, 'विकास करना है, लेकिन विरासत का संरक्षण करते हुए' और उनका यह मंत्र ही विकसित भारत के निर्माण का सच्चा मार्ग है। मुख्यमंत्री ने यज्ञों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि अगर धर्म के साथ विज्ञान होगा, तभी हम निर्धारित मुकाम या मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

उन्होंने गोझारिया गांव की खासियत की सराहना करते हुए कहा कि इस गांव में अपने काम को निर्विघ्न संपन्न करने की क्षमता तो है ही, साथ ही दूसरों के काम को भी पूरा करने की ताकत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राम मंदिर के निर्माण के बाद देश में व्याप्त नई ऊर्जा के संदर्भ में राष्ट्र निर्माण में गुजरात की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया 'विकसित भारत' का लक्ष्य 'विकसित गुजरात' के जरिए ही संभव होगा।

मुख्यमंत्री ने विकसित गुजरात के लिए हर गांव को विकसित बनाने और अंतिम छोर के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के सरकार के सार्थक प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

राज्य के आर्थिक विकास की गति को और तेज करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जोनवार वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत पहली कॉन्फ्रेंस हाल ही में उत्तर गुजरात में आयोजित की गई थी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि इस कॉन्फ्रेंस के परिणामस्वरूप तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ और 1200 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने उमिया माता से प्रार्थना की कि नववर्ष में गोझारिया गांव नए संकल्प ले और वे सभी संकल्प परिपूर्ण हों।

इस अवसर पर मेहसाणा के सांसद श्री हरिभाई पटेल ने कहा कि हम देश के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। इससे नई पीढ़ी में धार्मिक संस्कारों का सिंचन होता है। उन्होंने विकास की व्याख्या का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें केवल सड़क आदि ही नहीं, बल्कि धार्मिकता और संस्कार भी शामिल हैं।

राज्य सभा सांसद श्री मयंक नायक ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस युग में आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म की दिशा में मोड़ने के लिए शतचंडी महायज्ञ का आयोजन करने के लिए आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने एक सांसद के रूप में गांव के विकास के लिए सदैव उपलब्ध रहने और गोझारिया गांव विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए, इसके लिए संकल्पबद्ध होने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर उमिया माता के दर्शन किए और महायज्ञ के लिए उदार हाथों से दान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित भी किया। शतचंडी महायज्ञ के इस धार्मिक और भव्य कार्यक्रम में मेहसाणा के विधायक श्री मुकेश पटेल, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट बैंक के चेयरमैन श्री विनोदभाई पटेल, मेहसाणा के कलेक्टर श्री एस.के. प्रजापति, श्री उमिया माताजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पाटीदार समाज के अग्रणी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुंबई सेंट्रल पर हरित पहल को मिला नया आयाम, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीन स्थापित

(जीएनएस)। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के स्टाफ कैंटीन में एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर (OWC) मशीन स्थापित की गई है। यह पर्यावरण-संवेदनशील पहल भोजन और रसोई अपशिष्ट के जिम्मेदार प्रबंधन की दिशा में मंडल के प्रयासों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो रेलवे परिसर में स्वच्छ और हरित पर्यावरण को प्रोत्साहित करने की उसकी सतत प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करती है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पर्यावरण-अनुकूल जैविक अपशिष्ट परिवर्तक मशीन, रेलवे परिसर में खाद्य अपशिष्ट को कम करने और एक हरित एवं अधिक पर्यावरण-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगी। यह जैविक अपशिष्ट परिवर्तक पूरी तरह से स्वचालित, कॉम्पैक्ट और स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसे कैंटीन से निकलने वाले गीले और रसोई के कचरे को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन-वेसल डिहाइड्रेशन तकनीक का उपयोग करते हुए, यह मशीन जैविक कचरे को मिट्टी के पूरक या कम्पोस्टेबल बायोमास में बदल देती है, जिसका उपयोग कार्यालय परिसर में बागवानी और भूनिर्माण के लिए किया जा सकता है।

यह उन्नत कनवर्टर बिना किसी अतिरिक्त पदार्थ (जैसे चूरा या बैक्टीरिया) के काम करता है। यह गंध नियंत्रण, प्रेशर सील प्रोसेसिंग और शून्य गैस उत्सर्जन जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे निकास या जल निकासी प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह मशीन विभिन्न प्रकार के कचरे, जैसे कि रसोई के कचरे, बेकरी के सामान, टिशू पेपर और बगीचे के कचरे को संभालने में सक्षम है, जिससे कुशल और स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

इस अभिनव आंतरिक समाधान को लागू करके, पश्चिम रेलवे ने बाहरी कचरा संग्रहण सेवाओं पर अपनी निर्भरता सफलतापूर्वक समाप्त कर दी है और अपने कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी की है। यह पहल भारतीय रेल के पर्यावरणीय स्थिरता, आत्मनिर्भरता और संसाधन संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। पश्चिम रेलवे इस उपलब्धि के साथ स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है तथा रेलवे नेटवर्क में पर्यावरण के प्रति जागरूक परिचालन के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है।

महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, खिलाड़ियों को सुरक्षा के लिए प्रशासन से संपर्क रखने की सलाह

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने देशभर में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों और खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे कहीं भी खेल के लिए जाएं, उन्हें स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों को अपनी मौजूदगी की जानकारी देना चाहिए। उनका कहना है कि यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है और खेल समुदाय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

विजयवर्गीय ने बताया कि जैसे आम नागरिक अपनी यात्रा या किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को अपने कार्यक्रम के बारे में सूचित करते हैं, वैसे ही खिलाड़ियों को भी इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की लोकप्रियता और पहचान के कारण उनका ध्यान हमेशा आकर्षित होता है और इस वजह से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इंग्लैंड में फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ कई बार अनचाही घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटने और अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते देखा है। उसी तरह की परिस्थितियों का अंदेशा क्रिकेट खिलाड़ियों को भी रहना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जिस होटल में वे रुके थे, वहां अचानक कई युवा वहां आ गए और खिलाड़ियों के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक लड़की ने उनके सामने खिलाड़ियों को चूम लिया, जिससे उनकी पहचान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

कैलाश विजयवर्गीय ने जोर देकर कहा कि खेलकूद में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन, खेल संस्थान और स्थानीय अधिकारियों से भी अपील की कि वे खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध करें। उनका मानना है कि केवल नियम और आदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि हर खिलाड़ी और उसकी टीम को भी सुरक्षा के उपायों का पालन करना चाहिए।

इस घटना के बाद देशभर के खेल अधिकारियों और खिलाड़ियों के लिए यह चेतावनी और मार्गदर्शन का काम करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उनकी सुरक्षा के लिए सभी स्तर पर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी चाहे राष्ट्रीय हों या अंतरराष्ट्रीय, किसी भी देश या शहर में खेल आयोजन के दौरान स्थानीय प्रशासन से संपर्क और सुरक्षा उपायों की जानकारी लेना अनिवार्य होना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान न केवल महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि खेल जगत और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने का भी संकेत देता है। इसके साथ ही यह संदेश जाता है कि खेल में प्रतिभा के साथ-साथ सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सभी की साझा जिम्मेदारी है। इस तरह, इंदौर की घटना ने एक बार फिर खेल समुदाय और प्रशासन को सतर्क किया है और देशभर में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक बहस को जन्म दिया है।

मुरादाबाद में सिलेंडर फटने से रेस्टोरेंट में भीषण आग, एक महिला की मौत; परिवार के 10 सदस्य झुलसे

(जीएनएस)। मुरादाबाद। रामपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन के सामने रविवार रात एक भयावह अग्निकांड ने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया। परी रेस्टोरेंट के ऊपर बने मकान में आतिशबाजी की चिंगारी से गैस सिलेंडर में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में आग ने तबाही मचा दी। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव की मां मायादेवी की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के दस सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए।

जानकारी के अनुसार, प्रदीप श्रीवास्तव अपनी बेटी परी के नाम से दो मंजिला रेस्टोरेंट चला रहे हैं और परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता है। उसी समय रेस्टोरेंट के बराबर में एक वेक्यूएट हाल में बरात की तैयारी चल रही थी, जिसमें आतिशबाजी हो रही थी। चिंगारी रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल में जा गिरी और गैस सिलेंडर में आग लग गई।

कुछ ही समय में पांच सिलेंडर फट गए और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ग्यारह फायर टेंडर मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में फंसे लोगों को अग्निशमन कर्मियों ने तीसरी मंजिल से सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। झुलसे लोगों में रेस्टोरेंट मालिक प्रदीप श्रीवास्तव, उनकी पत्नी शिवानी सक्सेना, बच्चे परी और वैभव, बहन साधना, बहनोई सचिन भटनागर, पिता जयप्रकाश, भांजे शौर्य, अभिनव और वंश शामिल हैं। कई की हालत नाजुक बनी हुई है।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न होने और आतिशबाजी के कारण यह हादसा हुआ प्रतीत होता है।

स्थानीय लोग और प्रशासन आग जैसी आपदाओं से बचाव के लिए नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। घटना ने इलाके में भय और चिंता का माहौल बना दिया है, जबकि प्रशासन ने प्रभावित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।

नकवी का विपक्ष पर वार: कहा—'बिहार में गठबंधन हाथ मिलाकर नहीं, गला दबाकर हुआ', सपा को रामपुर में लगानी चाहिए स्टार प्रचारकों की प्रदर्शनी

(जीएनएस)। रामपुर/बरेली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। बिहार चुनाव के संदर्भ में उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, "यह गठबंधन हाथ मिलाकर नहीं, बल्कि गला दबाकर हुआ है।" नकवी ने दावा किया कि बिहार की राजनीति में इस बार "सामंती सुल्तानों की खटाखट गड़बड़ी और फटाफट हड़बड़ी" चौपाल पर औंधे मुंह गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में मतभेद ज्यादा और समझौते कम हैं। नकवी ने व्यंग्य करते हुए कहा, "महागठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा दरारें हैं। कांग्रेस और उसके साथी दल मुद्दों के दिवालियापन और नेतृत्व की कमी से जूझ रहे हैं। पूरा चुनाव ये मतभेद रफू करने में ही निकाल देंगे।"

रामपुर में सपा पर तंज कसते हुए नकवी बोले, "समाजवादी पार्टी ने बिहार में स्टार प्रचारकों की पूरी फौज भेज दी है, जबकि वहां वह चुनाव लड़ ही नहीं रही। रामपुर में एक 'स्टार चौराहा' है, इन्हें वहीं अपनी प्रदर्शनी लगा लेनी चाहिए।" उन्होंने आजम खान के "दिल जलने" वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, "दीप जल रहे हैं, मगर कुछ के दिल जल रहे हैं — ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं।"

"मुसलमानों से वोट थोक में लिया, विकास फुटकर में नहीं दिया"

नकवी ने कांग्रेस, सपा और राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने दशकों तक मुसलमानों से थोक में वोट तो लिए, लेकिन विकास फुटकर में भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, "भले ही कुछ लोगों ने भाजपा को वोट देने में कंजूसी की होगी, लेकिन भाजपा ने विकास में किसी से भेदभाव नहीं किया। अब मुसलमानों का बड़ा वर्ग समझ चुका है कि उनके हित में काम कौन कर रहा है।"

अखिलेश यादव पर पलटवार — "मंदिर बन गया, अब कुंठा झलक रही है"

अखिलेश यादव के अयोध्या भूमि विवाद और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "अखिलेश की समस्या भ्रष्टाचार नहीं, कुंठा है। पहले ये कहते थे — 'रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे'। अब मंदिर बन गया, तो इनके दिलों में जलन हो रही है।"
अखिलेश के आरोपों पर तंज कसते हुए नकवी ने कहा, "अगर सपा अपराध और कुशासन की बात करेगी, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सूप तो सूप, चलनी बोले जिसमें बहत्तर छेद।"

साध्वी प्राची और नंदी ने भी साधा सपा पर निशाना

इधर बरेली में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया। उन्होंने कहा, "सपा ने आजम खान को बिहार चुनाव का स्टार प्रचारक बनाकर साबित कर दिया कि वह हिंदुत्व के खिलाफ है। जब आजम जेल में थे, तब अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, अब सहानुभूति दिखा रहे हैं — यानी दाल में कुछ काला है।"
मदरसे में बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने की घटना पर उन्होंने तीखा सवाल उठाया, "क्या वे अपनी बेटी से भी ऐसा प्रमाण पत्र मांगेंगे?"
वहीं, कौशांबी में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा के स्टार प्रचारकों को "मूर्खों की फौज" करार दिया। उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति में लगे हैं। जनता अब वोट बैंक नहीं, विकास की बात चाहती है।"
नंदी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगा, क्योंकि देश का मतदाता अब "तुष्टिकरण नहीं, तरक्की" चाहता है।

निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा भारी: बीजेपी ने कहलगांव विधायक पवन यादव को छह साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित

(जीएनएस)। पटना/भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में बागी रुख अपनाना बीजेपी विधायक पवन यादव को महंगा पड़ गया। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। कहलगांव से मौजूदा विधायक पवन यादव ने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था, जिसे पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन के हितों के खिलाफ माना। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि "पवन यादव का निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना पार्टी अनुशासन और गठबंधन की एकजुटता के विपरीत है। इस कदम से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। अनुशासन समिति की सिफारिश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से छह वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।" यह आदेश सभी जिला संगठनों और संबंधित पदाधिकारियों को भी भेज दिया गया है ताकि कार्रवाई का पालन सुनिश्चित हो सके।

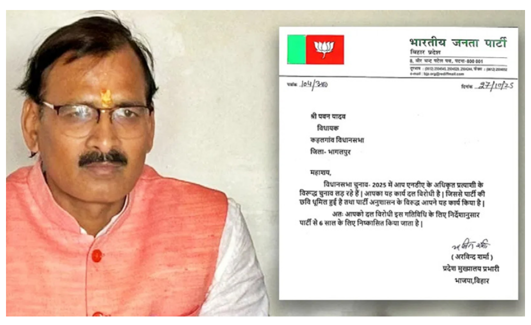

कहलगांव में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। स्थानीय स्तर पर माना जा रहा है कि पवन यादव के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से एनडीए उम्मीदवार की स्थिति कमजोर हो सकती थी और वोटों का बंटवारा होने की आशंका थी।

टिकट कटने के बाद जताई थी नाराजगी

टिकट से वंचित होने के बाद पवन यादव ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा था — "किसी को टिकट मिलने से ज्यादा, मेरे टिकट न मिलने की चर्चा हो रही है। यह राजनीति नहीं, बल्कि आप सबके अथाह प्यार और विश्वास का परिणाम है। पद मिलना सौभाग्य हो सकता है, लेकिन जनता के दिलों में जगह बनाना वरदान होता है। मैं अपनी पहचान पद से नहीं, अपने कर्म और सेवा से बनाऊंगा।"

2020 में दर्ज की थी ऐतिहासिक जीत

पवन यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहलगांव से सबसे अधिक मतों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 43 हजार मतों से हराया था। उस समय उनकी जीत को बीजेपी की बड़ी उपलब्धि माना गया था। हालांकि, इस बार एनडीए गठबंधन ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे वे नाराज हो गए और बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली नेता क्यों न हों। कहलगांव की राजनीति में यह फैसला नए समीकरण खड़ा कर रहा है और आगामी दिनों में इसका असर क्षेत्रीय वोटिंग पैटर्न पर भी देखने को मिल सकता है।

दरभंगा में खरना की रात लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, छह घर जलकर खाक ,गनीमत रही, जनहानि नहीं हुई

(जीएनएस)। दरभंगा। छठ पर्व के खरना की रात बिहार के दरभंगा जिले में अचानक लगी आग ने उत्सव की खुशियों को मातम में बदल दिया। बहेड़ी थाना क्षेत्र के रजखा मखनाहा गांव में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, आग लगने के बाद एक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिससे लपटें और भी तेज हो गईं और पूरा इलाका दहशत में आ गया।
घटना के वक्त अधिकांश लोग खरना के प्रसाद की तैयारी में जुटे थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। लोग घरों से बाहर निकलकर जान बचाने के लिए भागे। मौके पर चीख-पुकार मच गई और गांव के लोग एकजुट होकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे।
एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया,

"सिलेंडर फटने की जोरदार आवाज आई। जब बाहर निकली तो आग चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने तुरंत अपने परिवार को लेकर बाहर भागकर किसी तरह जान बचाई।" उन्होंने बताया कि लपटें इतनी तेज थीं कि पानी डालने या सामान निकालने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। कुछ ही देर में छह घर जलकर पूरी तरह खाक हो गए।
गांव के लोगों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय स्तर पर काफी प्रयास किए गए, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लपटें इतनी तेज हो गईं कि कोई नजदीक नहीं जा सका। बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। हालांकि, इस हादसे में किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कई परिवारों के घर, सामान और पूजा की सारी तैयारियां जलकर राख हो गईं।
उधर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी आग की एक बड़ी घटना सामने आई है। रविवार देर रात एक होटल में अचानक आग लग गई। इस हादसे में आठ लोग झुलस गए और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दमकल विभाग की टीम ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दरभंगा की यह घटना छठ पर्व के शुभ अवसर पर लोगों के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गई। प्रशासन ने राहत व पुनर्वास की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी ठहराव और खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने आग को और भी भीषण बना दिया।

इंदौर में बिना अनुमति पब गईं विदेशी खिलाड़ी, छेड़छाड़ कांड के बाद पुलिस ने निकाले सीसीटीवी फुटेज

(जीएनएस)। इंदौर। आईसीसी महिला विश्व कप में हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना के बाद अब सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि कई विदेशी खिलाड़ी बिना अनुमति और सुरक्षा सूचना के पब और बारों में पार्टी करने गई थीं। इस लापरवाही के चलते अब पुलिस ने उन सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इंदौर में खेले गए पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम की कुछ खिलाड़ी सी-21 मॉल स्थित एक पब में गई थीं, जहां उन्होंने घंटों पार्टी की और डांस किया। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका टीम की कुछ खिलाड़ी भमौरी स्थित एक पब में गई थीं। इन गतिविधियों की न तो स्थानीय पुलिस को पूर्व जानकारी थी, न ही टीम के सुरक्षा अधिकारियों को इसकी कोई सूचना दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही असहज और खतरनाक स्थितियां पैदा कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया टीम की दो खिलाड़ियों के साथ अकील खान नामक युवक ने छेड़छाड़ की थी। दोनों खिलाड़ी उस समय होटल से अकेले ड्रिंक लेने के लिए बाहर निकली थीं। उनके साथ न कोई सुरक्षा अधिकारी था, न पुलिस का वाहन। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसने सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्रिकेट प्रबंधन सूत्रों का कहना है कि हर अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होता है। साथ ही आईसीसी और स्थानीय पुलिस अधिकारी मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हैं। फिर भी कई बार खिलाड़ी निजी मुलाकातों या पसंदीदा जगहों पर घूमने के लिए गुपचुप तरीके से निकल जाते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ जाती है।
इंदौर में हाल ही में तीन ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत उजागर की। पहला मामला इंग्लैंड टीम का था, जिसने विनस स्पोर्ट्स एरीना जाने की अनुमति मांगी। पुलिस और प्रशासन ने जांच के बाद अनुमति दी और टीम सुरक्षा घेरे में वहां गई। दूसरे मामले में एक अन्य टीम ने सराफा बाजार जाने की इच्छा जताई, लेकिन सुरक्षा कारणों से मना कर दिया गया और उन्हें वही व्यंजन होटल में उपलब्ध कराए गए। तीसरा और सबसे विवादास्पद मामला ऑस्ट्रेलिया टीम की दो खिलाड़ियों का रहा, जो बिना सूचना और सुरक्षा घेरे के होटल से बाहर निकलीं और छेड़छाड़ की शिकार बन गईं। विश्व कप आयोजन से पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए), पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक में यह तय किया गया था कि कोई भी टीम जोखिमभरे या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना अनुमति नहीं जाएगी। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए होटल, बस और स्टेडियमों में विशेष सुरक्षा बल तैनात हैं। इसके बावजूद खिलाड़ियों द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी अब पूरे मामले को संवेदनशील बना रही है।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता और सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी किसी बड़े विवाद या खतरे का कारण बन सकती है।

साइबर ठगी का कंबोडिया कनेक्शन: विदेश से हो रहे कॉल, भारतीय खातों में पहुंच रहा पैसा, 1054 करोड़ की ठगी में सिर्फ 1.94 करोड़ की रिकवरी

(जीएनएस)। ग्वालियर। देशभर में तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी की वारदातों का अब अंतरराष्ट्रीय चेहरा सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हो रही अधिकांश डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं के तार कंबोडिया से जुड़े हैं। वहां से ठग वाइस और वीडियो कॉल के जरिए भारतीय नागरिकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, जबकि ठगी की रकम भारतीय बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। यानी अपराधी विदेश में सुरक्षित रहते हुए भारत में बैठे एजेंटों और फर्जी खातों के जरिए यह साइबर नेटवर्क चला रहे हैं।
मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में दर्ज मामलों की जांच में सामने आया है कि अधिकांश कॉल कंबोडिया से आ रहे हैं। मप्र पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां फिलहाल सिर्फ उन खातों तक पहुंच पा रही हैं, जिनमें

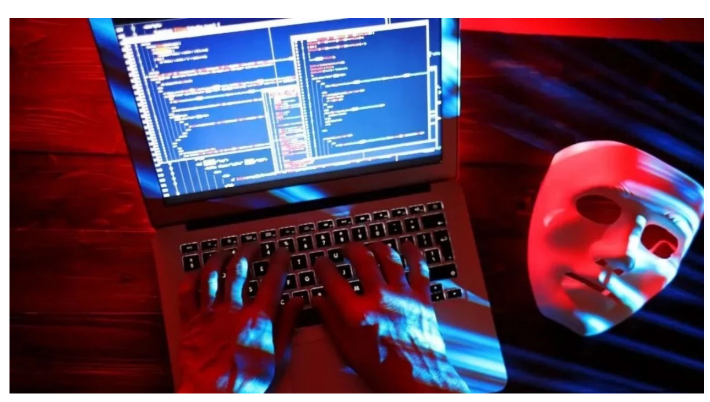

पैसा ट्रांसफर हुआ। लेकिन विदेश में बैठे मास्टरमाइंड्स तक पहुंचना अभी मुश्किल बना हुआ है।
इन फर्जी खातों के लिए ठग बेरोजगार युवाओं, छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बना रहे हैं। मामूली कमीशन या जॉब ऑफर के लालच में ये युवा अपने बैंक खाते दूसरों के इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। इसी के माध्यम से ठग पैसे को कई परतों में घुमाकर अंततः क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिये विदेश भेज देते हैं।
नईदुनिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में हुई साइबर ठगी की करीब 95 प्रतिशत वारदातों में कॉल कंबोडिया या दुबई जैसे देशों से आए। सिर्फ ग्वालियर जिले की ही 11 प्रमुख घटनाओं में कॉल का सोर्स कंबोडिया रहा।
इन घटनाओं से साफ झलकता है अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क —
1.ग्वालियर के रामकृष्ण मिशन स्कूल के सचिव सुप्रदिप्तानंद से 2.52 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर वाइस और वीडियो कॉल कंबोडिया से किए गए थे।
2.ग्वालियर की शिक्षिका आशा भटनागर से 2024 में 51 लाख रुपये ठगे गए। कॉल कंबोडिया और दुबई से आए, जबकि मास्टरमाइंड भारत के भिलाई से था। ठगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा दुबई भेजा।
3.दिल्ली के गुलमोहर पार्क निवासी 78 वर्षीय नरेश मल्होत्रा को एक माह तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 22.92 करोड़ रुपये की ठगी की गई। उनके पास लगातार कॉल कंबोडिया से आते रहे।
साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली बेहद संगठित और तकनीकी हो चुकी है। ठगी की रकम आमतौर पर छह से सात परतों में अलग-अलग खातों में भेजी जाती है ताकि उसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। इसके बाद वह रकम क्रिप्टोकरेंसी के जरिये विदेश पहुंचा दी जाती है।
मध्य प्रदेश में 1 मई 2021 से जुलाई 2025 तक 1054 करोड़ रुपये की साइबर ठगी दर्ज की गई है, जबकि अब तक मात्र 1.94 करोड़ रुपये की ही रिकवरी हो पाई है। यानी कुल ठगी गई राशि का 0.18 प्रतिशत से भी कम पैसा वापस मिल सका है।
साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अब केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक वैश्विक संगठित आपराधिक नेटवर्क है जो भारत को टारगेट बना रहा है। जांच एजेंसियों को अब अंतरराष्ट्रीय सहयोग और डिजिटल फॉरेंसिक इंटेलिजेंस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि विदेशों से संचालित इन 'कंबोडिया नेटवर्क्स' पर अंकुश लगाया जा सके।

1 नवंबर से बैंकों में लागू होंगे नए नियम, खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता में आएगा बड़ा बदलाव

(जीएनएस)। नई दिल्ली। 1 नवंबर 2025 से देश के सभी बैंकों में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाओं और उनके धन की सुरक्षा पर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहकों के लिए भरोसेमंद बनाना है। नए नियमों के तहत खाताधारक अब अपने बैंक खाते में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) जोड़ सकेंगे। इससे पहले यह सीमा केवल दो थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से दावा निपटान प्रक्रिया तेज और सुव्यवस्थित होगी और किसी भी अनधिकृत दावे या विवाद का समाधान आसानी से संभव होगा। बैंकों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों के तहत नॉमिनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना भी अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी इमरजेंसी या क्लेम की स्थिति में बैंक तुरंत नॉमिनी से संपर्क कर सके और राशि की ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इससे खाताधारकों की जमा पूंजी की सुरक्षा बढ़ेगी और क्लेम निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बैंक विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों

के लिए फायदेमंद है, जिनके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं या जो अपने धन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहते हैं।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी और जमाकर्ताओं को अपनी जमा पूंजी पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि अब खाताधारक अपने परिवार, मित्र या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, जिससे उनकी जमा राशि सुरक्षित रहे और किसी भी विवाद की स्थिति में दावा निपटान प्रक्रिया आसान हो। इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत बैंकों को चार नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति दी गई है। सभी बैंकियों को यह बदलाव 2025 के अंत तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। पुराने नियमों में केवल दो नॉमिनी रखने की सीमा थी, जिससे कई मामलों में क्लेम निपटान में देरी होती थी और विवाद पैदा हो जाता था। नए नियमों के लागू होने के बाद ऐसे मामलों में बैंक तुरंत कार्रवाई कर सकेगा। साथ ही खाताधारक अपनी जमा पूंजी पर अधिक नियंत्रण और सुरक्षा महसूस करेंगे। इस बदलाव के लागू होने के साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए सूचना अभियान भी चलाएंगे। ग्राहकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ें और उनके मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अपडेट करें। बैंक अधिकारी यह भी बताएंगे कि किस प्रकार नॉमिनी विवरण अपडेट करने से क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में राशि का ट्रांसफर त्वरित रूप से किया जा सकेगा। बैंकों में यह बदलाव वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही ग्राहक अपनी जमा पूंजी के संबंध में अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि महसूस करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में इस बदलाव से बैंकिंग सेवाओं में नई पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के लिए प्रक्रिया सरल और सहज होगी। इस तरह, 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए बैंकिंग नियम न केवल खाताधारकों की सुरक्षा बढ़ाएंगे, बल्कि बैंकिंग प्रणाली को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ग्राहक अब अपने नॉमिनी विवरण अपडेट करके अपने धन को सुरक्षित कर सकेंगे और किसी भी विवाद या इमरजेंसी की स्थिति में आसान और त्वरित समाधान पा सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास और सुरक्षा की नई दिशा को संकेत करता है और ग्राहकों को अपनी वित्तीय योजनाओं में अधिक नियंत्रण और भरोसा प्रदान करेगा।

बिहार चुनाव में बनारस की मुस्लिम महिलाओं का सशक्त कदम: घर-घर जाकर प्रचार करेगी योगी सरकार की नीतियां

(जीएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने चरम पर पहुँच चुका है और इस बार वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने राजनीतिक परिदृश्य में अपनी एक नई भूमिका निभाना शुरू कर दी है। बनारस के बजरडीहा इलाके की ये महिलाएं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी हैं और उन्होंने पश्चिम बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर लोगों से सीधे संवाद करने का बीड़ा उठाया है। उनका मकसद यह है कि मुस्लिम समाज को यह जानकारी मिले कि योगी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने और समाज में सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
इन महिलाओं को समूहों में बांटकर 25-25 की टीम बनाई गई है, जो चार-पांच टीमों के रूप में अलग-अलग इलाकों में सक्रिय हैं। वे घर-घर जाकर आम लोगों से मिलती हैं, उनके सवाल सुनती हैं और उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों की जानकारी देती हैं। उनका मानना है कि लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझाना और संवाद करना, बड़े सभाओं या प्रचार पत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। वे बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में योगी सरकार ने किस तरह क्रांतिकारी पहल की हैं, और इनसे समाज के कमजोर वर्गों का जीवन कैसे बदल रहा है।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना और तीन तलाक पर रोक जैसी पहलों ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। पहले महिलाएं बीमारी और सामाजिक पाबंदियों

के कारण अपने घरों में कैद रहती थीं, लेकिन अब आयुष्मान योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। तीन तलाक कानून लागू होने के बाद महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा बढ़ी है, जिससे वे अपने जीवन और परिवार के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
महिलाओं का कहना है कि वे पश्चिम बिहार के गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को बताएंगी कि यूपी मॉडल के तहत विकास कैसे हुआ और यह किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। वे अपील करेंगी कि बिहार में भी एनडीए की सरकार लाकर इसी तरह की विकास गति हासिल की जाए। उनका मानना है कि मुस्लिम महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि उनके हित में काम कौन कर रहा है और उनके अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है। इस प्रचार अभियान के माध्यम से वे अपने समाज के बीच एक सकारात्मक संदेश फैलाना चाहती हैं कि बदलाव संभव है और इसके लिए सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है और इस समय वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भाजपा के प्रचार अभियान में एक नया मोड़ ला सकती है। उनके घर-घर जाकर किए जा रहे प्रचार से न केवल पार्टी के एजेंडे को मजबूती मिलेगी, बल्कि समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सक्रिय भूमिका का संदेश भी फैल सकेगा। इन महिलाओं की तैयारी और उनके प्रचार अभियान की कहानी भी दर्शनीय है। सुबह से रात तक वे ग्रामीण इलाकों में लोगों से मिलती हैं, उनके सवाल सुनती हैं, योजनाओं की जानकारी देती हैं और स्थानीय समस्याओं को समझती हैं। यह कार्य न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में बदलाव की उम्मीद भी जगाता है। बिहार के चुनावी माहौल में इस तरह की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि महिलाएं अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि परिवर्तन के सूत्रधार बन रही हैं।
वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं का यह अभियान केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं है। यह समाज में जागरूकता फैलाने और महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी भी है। उनके प्रयास यह संदेश देते हैं कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सीधे आम लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। यह पहल महिलाओं के नेतृत्व और उनके समाज में बदलाव लाने की क्षमता को उजागर करती है।
इन महिलाओं के अभियान में हर रोज़ की चुनौतियां, ग्रामीण इलाकों की कठिनाइयाँ, और मतदाताओं के साथ संवाद की प्रक्रिया इस खबर को और जीवंत बनाती है। यह दर्शाता है कि बिहार में चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि समाज सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं का यह सक्रिय कदम न केवल चुनाव में नए रंग भरता है, बल्कि यह यह संदेश देता है कि समाज में बदलाव और विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है।
इस अभियान की सफलता चुनावी रणनीति और समाज में महिलाओं के योगदान की मिसाल बनेगी। उनकी मेहनत, लगन और जागरूकता आने वाले समय में अन्य जिलों और राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इस तरह, बनारस की मुस्लिम महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल चुनावी मोर्चे पर महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद और बदलाव की कहानी भी पेश करती है।